

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4226

बुधवार, 26 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

नए अंतरिक्ष कानून का मसौदा

4226. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री इमरान मसूद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नए अंतरिक्ष कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की समय-सीमा क्या है तथा यह छह वर्ष पहले तैयार किए गए प्रारंभिक संस्करण से किस प्रकार भिन्न है;
- (ख) नए मसौदा कानून में विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करने तथा भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं;
- (ग) अंतरिक्ष क्षेत्र में बेहतर अनुपालन और शासन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केन्द्र (इन-स्पेस) को क्या-क्या विनियामक और दण्डात्मक शक्तियां दिए जाने का प्रस्ताव है; और
- (घ) अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष की स्थिति तथा परिचालन रूपरेखा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क), (ख) एवं (ग)

इस क्षेत्र में यह पहला विधेयक होने के कारण, सरकार इसकी गहनता से जांच कर रही है तथा सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

- (घ) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और डीपीआईआईटी ने इस उद्देश्य के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार ₹1,000/- करोड़ के उद्यम पूंजी कोष के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में मेसर्स सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के चयन हेतु इन-स्पेस बोर्ड की मंजूरी पर सहमति जताई है। इससे आगे की प्रक्रिया चल रही है।
